

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनुपचारिक
रूप में
परामर्शित।

पत्रांक - प्र2/बोर्ड-विविध-17/2012

पटना, दिनांक -

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0मी0 ग्रिड सब स्टेशन सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में एक-एक अतिरिक्त 33 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं अन्य 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फूलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पाँच 33 के0मी0 लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

राज्य के सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के0मी0 ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर का व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 33 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। अन्य 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फूलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पाँच 33 के0मी0 लाईन "बे" बनाने की योजना है। इस प्रकार 33 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" पाँच अदद एवं 33 के0मी0 लाईन "बे" पाँच अदद का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 3.70 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के समर्थक उल्लेखित 132/33 के0मी0 5 ग्रिड सब-स्टेशन में एक-एक अतिरिक्त 33 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं पाँच 33 के0मी0 लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्मुग्तान एवं सूद का भुग्तान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुग्तान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुग्तान करने पर ब्याज दर में 1/4 (वोधाई) प्रतिशत छूट होगी।



Acc. (R)

24/7

3272/M(F&R)
24/6/12

015/FCCP
25-7-12

D(L)

24/7

24/7

24/7

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य विद्युत् पर्यद को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।
6. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 749 दिनांक 26.6.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-17/2012

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 23/7/12

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-17/2012 3117

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य (विद्युत्) बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/ आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

20/7/12

23.07.12

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र2/बोर्ड-विधि-18/2012

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग
द्वारा
अनुमोदित
रूप से
प्रमाणित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द मटेल मार्ग, पटना।

विषय:

सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त 132 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" के निर्माण की कुल 5.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

राज्य में विद्युत मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यरत सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के0मी0 ग्रिड उपकेंद्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेंद्रों में 50 एम0बी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय राग विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 132 के0मी0 के पाँच अदद ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 5.00 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त 132 के0मी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" के निर्माण की कुल 5.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकारगी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (जेथार्ड) प्रतिशत छूट होगी।

कल/10/10/12



F-11
24/7

3241/M(FAR)
24/07/12
2016/FCR
25-7-12

D(L)
24/7
2016/FCR

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य विद्युत् पर्वत को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।
6. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 750 दिनांक 26.6.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-18/2012

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-18/2012

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

4381
26.09.12

पत्रांक - प्र02/बोर्ड विविध-14/2012

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आवेदः

स्वीकृत।

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2x195 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट लगायी जा रही है। पहली इकाई से उत्पादन का लक्ष्य जून 2013 एवं दूसरे इकाई से उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर 2013 है। इन नयी इकाईयों से बिजली की निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली का उपयोग हो सके। वर्तमान में 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0-गोपालगंज, 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0-दरभंगा, एवं 132 के0भी0 एम0टी0पी0एस0 - एस0के0एम0सी0एच0 के दूसरे सर्किट का रिकंडक्टिंग कर उत्पादित बिजली को गोपालगंज, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पहुँचायी जा सके।

2. उपरोक्त नई यूनिटों से होने वाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली के निर्माण के बिना उत्पादित होने वाले विद्युत् की निकासी एवं उपयोग संभव नहीं है। इस कारण काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड के दोनों नई इकाईयों के चालू होने के पहले संचरण प्रणाली का निर्माण एवं सुदृढीकरण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली की निकासी ससमय हो सके। इस कार्य हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 26,11,93,744.00 (छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख तीरानवें हजार सात सौ चौवालीस) मात्र आकलित की गई है।

3. उक्त आलोक में काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन की निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूँकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

कृ०पृ०उ०

सदस्य (सि०)

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड

8071

- 2 -

- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूट देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य विद्युत पर्यद को परियोजनाओं हेतु ऋण-राज्य योजना मांग सं0-10-विपत्र कोड पी0 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN -0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 9016 दिनांक 14.08.12 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-14/2012

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-14/2012 436/ दिनांक 28/9/12

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आइ0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

28/9/12

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाईस लाख रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2x195 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट लगायी जा रही है। पहली इकाई से उत्पादन का लक्ष्य जून 2013 एवं दूसरे इकाई से उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर 2013 है। इन नयी इकाईयों से बिजली की निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली का उपयोग हो सके। वर्तमान में 220 के०भी० एम०टी०पी०एस०-गोपालगंज, 220 के०भी० एम०टी०पी०एस०-दरभंगा, एवं 132 के०भी० एम०टी०पी०एस०-एस०के०एम०सी०एच० के दूसरे सर्किट का रिकंडक्टिंग कर उत्पादित बिजली को गोपालगंज, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पहुँचायी जा सके।

2. उक्त आलोक में राज्यादेश संख्या-4361 दिनांक 26.09.2012 द्वारा काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन की निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कालान्तर में कार्यान्वयन के दौरान कुछ उपस्करों की मात्रा में बढ़ोत्तरी के कारण योजना की कुल लागत ₹ 28,39,51,784.54 हो गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाईस लाख रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क०प०ऊ०

5. इस राशि की निशान्ती उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गौंधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आई०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012 के पृष्ठ संख्या 22/टि० पर दिनांक 19.09.2014 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012 के पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक 05.12.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 26/12/2014

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012 5480

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बोर्ड-विविध-94/10

पटना, दिनांक -

विभाग द्वारा सेवा में,
नौपचारिक रूप
से परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

C.E. (Tb.) / C.E. (O.A.)

F. C. (P) / F. C. (P)

C.E. (P) / C.E. (P)

बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण हेतु कुल 1.72 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाईन के दो क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण की योजना है। इसके लिए दो अदद पाइल फॉउन्डेशन होना है। कार्य पूरा होने की स्थिति में मुजफ्फरपुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं निर्माणाधीन एस0के0एम0सी0एच0 ग्रीड उपकेन्द्र आपरा में जुट पायेंगे जिसके कारण मुजफ्फरपुर इलाके में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षित सुधार होगा। इस योजना की कुल लागत 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रुपये है।

उक्त आलोक में बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण हेतु कुल 1.72 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

कृपयुक्त

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800 विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष-0101 बिहार राज्य विद्युत पर्वत को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801008000101 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 808/(बजट पदाधिकारी), दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3608 दिनांक 16/8/11

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियां में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र2/बोर्ड-विविध-93/10

पटना, दिनांक - _____

वित्त विभाग
द्वारा सेवा में,
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

C.E.(Tr.) / C.E.(D.M.)

विषय:

सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 4.15 (चार करोड़ पन्द्रह लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बागमती नदी के तटबंधों का विस्तार और बाढ़ निरोधक कार्य होने से 132 के0 भी0 संचरण लाइनों के टावरों की ऊँचाई कम हो गयी है। इन टावरों की ऊँचाई बढ़ाने से संचरण लाइन सुरक्षित रूप से कार्य करने एवं जान-माल की क्षति रोकने हेतु सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत आठ 132 के0 भी0 संचरण लाइन के टावर एवं छः पाइल फाउण्डेशन तथा दो आपेन फाउण्डेशन का निर्माण किया जाना है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती बांध योजना का विस्तार का कार्य किया गया।

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा अविलम्ब टावरों की ऊँचाई बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिए बागमती तटबंध विस्तार योजना को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम-विकास योजना के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर में निर्माणाधीन ग्रीड उपकेन्द्र से विद्युत् आपूर्ति चालू की जा सकेगी तथा ग्रीड उपकेन्द्र को एस0के0एम0सी0 हॉस्पिटल में बनने वाले ग्रीड को जोड़ा जा सकेगा।

उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 1556 दिनांक 29.03.2011 द्वारा सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 4.15 (चार करोड़ पन्द्रह लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की जाती है।

चूँकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निवासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3257/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-93/10

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 10/8/11

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-93/10 3607

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

10/8/11

पत्रांक - प्र02/बोर्ड-विविध-35/10

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

C.E.(Jr)/K.E.(D.M.)

विषय-

टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 27.67 (सताईस करोड़ सरसठ लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण प्रणाली के सृद्धीकरण, निमित्त संचरण की संरचना में व्यापक विस्तार हो रहा है। संचरण प्रणाली में बढ़ते हुए विद्युत मांग के आलोक में टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनुरोध किया गया है। टेहटा (जहानाबाद) में ग्रिड सब स्टेशन एवं पटना-गया 132 के0भी0 संचरण लाईन से जोड़ने हेतु LILO व्यवस्था के निर्माण के लिए 18.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। इसी प्रकार इमामगंज (गया) में ग्रिड सब स्टेशन एवं इमामगंज-शेरघाटी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 32.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। अतः इस योजना की कुल लागत 51.20 करोड़ रुपये है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 4607 दिनांक 30.11.2010 द्वारा टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 1 (एक) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 27.67 (सताईस करोड़ सरसठ लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102 बिहार राज्य विद्युत परषद को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801007890102 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3276/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3609 दिनांक 10/8/11

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रति में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बोर्ड-विधि-57/10

पटना, दिनांक - _____

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में 3.10 (तीन करोड़ दस लाख) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण, संवरण एवं वितरण हानी में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 4805 दिनांक 30.11.2010 द्वारा बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 3.10 (तीन करोड़ दस लाख) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102 बिहार राज्य विद्युत पर्यद को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801007890102 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3267/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक3.6.11..... दिनांक10/8/11.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियां में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित।

पत्रांक - प्र02/बोर्ड-विविध-18/10 3612
सेवा में,

पटना, दिनांक - 10/8/11

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011-12 में ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जन्दाहा अवस्थित पॉवर सब स्टेशन भी विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं है। जन्दाहा की दूरी भी कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से अधिक है। इस कारण भी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बिजली बाधित रहती है। जन्दाहा कृषि आधारित एक बड़ा क्षेत्र है। जहाँ बिजली की संतोषजनक व्यवस्था के लिए ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जन्दाहा के 10-15 कि0भी0 की परिधि में कई पॉवर सब स्टेशन अवस्थित हैं जन्दाहा में ग्रिड उन्हें एक सुदृढ़ श्रोत प्रदान करेगा। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 3427 दिनांक 18.08.2010 द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना 25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकायें ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति कं देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसका पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद र पारम्भ होगी।

- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
 (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सू देय होगा।
 (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छू होगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-010: बिहार राज्य विद्युत पर्यद को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 680100789010: विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि र विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 ए आइ०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा क जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3277/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3612 दिनांक 10/8/11

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

Filed
15/03/2011

पत्रांक - प्र2/विद्युत बोर्ड-16/2002

पटना, दिनांक -

सेवा में

15/03/2011

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द्र प्रदेल मार्ग, पटना।

विषय:

132/33 के०भी० शेरघाटी ग्रीड उपकेन्द्र एवं 132 के०भी० बोधगया-शेरघाटी संचरण लाईन का राज्य योजना के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्य की योजना को पुनरीक्षित लागत 25.10 करोड़ रुपये पर पूरा करने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 11.10 करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या 80 दिनांक 31.03.2003 द्वारा 132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र शेरघाटी एवं 132 के०भी० द्विपरिपक्षीय संचरण लाईन के निर्माण हेतु 14.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्वीकृति किया गया था। राज्यादेश संख्या 129 दिनांक 31.03.2005 द्वारा 2.17 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या 24 दिनांक 03.01.2007 द्वारा 9.83 करोड़ रुपये विद्युत बोर्ड को विमुक्त किया गया है। इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है परन्तु योजना लागत में बढ़ोतरी के कारण योजना को पूरा नहीं किया जा सका। इस योजना की पुनरीक्षित लागत 25.10 करोड़ रुपये हो गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस कार्य को पूरा करने हेतु 11.10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के०भी० शेरघाटी ग्रीड उपकेन्द्र एवं 132 के०भी० बोधगया-शेरघाटी संचरण लाईन का राज्य योजना के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्य की योजना को पुनरीक्षित लागत 25.10 करोड़ रुपये पर पूरा करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं इस योजना को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 11.10 करोड़ रुपये (ग्यारह करोड़ दस लाख रु०) ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 4/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801008000101 विषय शीर्ष-5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. वित्त विभाग के परामर्शानुसार राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र२/विद्युत् बोर्ड-16/2002

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र२/विद्युत् बोर्ड-16/2002 1501 दिनांक 26/3/11

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग



बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

दिनांक.....

पत्रांक...../सं०
प्र०-२/वि०बोर्ड-०४/२००३

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा -

वित्त विभाग।

विषय:-

वित्तीय वर्ष २००६-०७ में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण/वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ९.८३ करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु ९.८३ करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रुपये के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २००६-०७ में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ९.८३ करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए ९.८३ करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रुपये मात्र व्यय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत १३२/३३ कै०भी० ग्रीड उपकेन्द्र शेरघाटी का निर्माण किया जाएगा।

यह राशि बजट शीर्ष - ६८०१ - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - राज्य योजना - ८०० - विद्युत बोर्डों के लिये अन्य कर्ज - ०१०१ - बिहार राज्य विद्युत पर्यटन को ऋण - मांग सं०-१० - विपत्र कोड पी०-६८०१००८०००१०१ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २००६-०७ के उपबद्धित राशि से विकलनीय होगा।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एफ-४-९८-८८-३८८१ दिनांक ०७.०७.१९८९ के अनुसार पूर्व में दिये गये ऋण के मूल सृद्ध की वास्तव प्रसंगाधीन राशि से २५ प्रतिशत की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्यटन को छुट प्रदान की जाती है। ऋण की शर्त निम्नवत होगी :

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सृद्ध का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि के एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस ऋण पर १३ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर २.५ प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सृद्ध देय होगा।

इस राशि की निकासी मुख्य अभियन्ता के सचिव (प्राथमिक) ऊर्जा विभाग के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को किया जायेगा।

३९/म(फ)
०५/०१/०७

७५/फ/८७
३१/१०/७

१५/८/८८
३१/१०/७

४०/८/८८
३१/१०/७

6. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय अन्य परियोजना में नहीं किया जायेगा।
7. योजना का कार्यान्वयन "टर्न की" के आधार पर किया जायेगा। राज्य विद्युत बोर्ड कार्य का सम्पादन कर स्वीकृत राशि का उपयोग फरवरी, 2007 तक सुनिश्चित करेगा।
8. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्राथमिक) ऊर्जा विभाग, पटना, के पदनाम से रु० 9.83 करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रुपये का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक -
प्र०-2/वि०बोर्ड-04/2003.

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक -
प्र०-2/वि०बोर्ड-04/2003.

पटना, दिनांक 3/1/07

प्रतिलिपि :- सदस्य (वित्त), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रा०), ऊर्जा विभाग/निबंधन/प्रशाखा-7/बजट शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा-7, वित्त/राजस्व शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-पू2/विद्युत बोर्ड-4/003-

पटना, दिनांक

सेवा में,

मौखिक स्तर
परामर्शित।

महामहोदय,
बिहार, पटना।

द्वारा: x वित्त विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-2005 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संवरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 14.00 करोड़/बोर्ड करोड़ रुपये में से 2.17 करोड़/दो करोड़ सतरह लाख रुपये व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

निष्णानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग के राज्यदेश संख्या-80 दिनांक 31.3.2003 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संवरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 132/33 के.भी. का ग्रिड उपकेन्द्र गोरघाटी, 132 के.भी. दिक्खरिपल्ली संवरण लाइन के लिए 14.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़/दो करोड़ रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा उक्त संवरण लाइन के लिए वित्तीय वर्ष 2004-2005 में पुनः 2.17 करोड़/दो करोड़ सतरह लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राशि बजट शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए एवं राज्य योजना-000-विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज-0101-बिहार राज्य विद्युत पर्यव को रूप मांग संख्या-10, विवरण कोड सं.पी. 6801008000101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 के उपबंधित राशि से आवंटन के आधार पर होगा।

3. वित्त विभाग के परीपत्र संख्या-एफ-4-98-88-3881 दिनांक 7.7.89 के अनुसार पूर्व में दिये गए रूप के मूल एवं सूद की बाबत प्रसंगाधीन राशि से 25 % की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्यव को हट दी जाती रही है, जिसे जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

रूप की शर्तें निम्नवत होगी :-

[क] रूप का पुर्णमुताबक एवं सूद का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी रूप श्रम निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

[ख] इस रूप पर 13 % की दर से वार्षिक व्याज देय होगा।

[ग] समय पर भुगतान नहीं करने पर 25 % की दर से क्लिम्ब दंड देय होगा।

4. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव/पाठ उर्जा विभाग के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिवाई भवन, पटना से की जायेगी। जिसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंक चेक के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को किया जायेगा।

5. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय अन्य परियोजनाओं में नहीं किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव, प्राविधिक, उर्जा विभाग में पटना के पदनाम से 2.17 करोड़ रुपये करोड़ सतरह लाख रुपये का प्राधिकार पत्र गीला निगति करने की कृपा की जाय।

EO/-

॥ के० सी० मिश्र ॥
सरकार के सचिव।

आपांक- 92/विद्युत बोर्ड-4/003-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

EO/-

॥ के० सी० मिश्र ॥
सरकार के सचिव।

आपांक- 92/विद्युत बोर्ड-4/003-129

पटना, दिनांक 3/3/05

प्रतिलिपि- सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/लेखा पदाधिकारी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव, प्राविधिक, उर्जा विभाग, पटना/निर्बंधक, उर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, उर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, तीन प्रतियों में उर्जा विभाग, पटना/गार्ड फाईल, उर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, पटना/प्रशाखा-7 वित्त विभाग, पटना/राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

P. Misra
3/3/05
॥ के० सी० मिश्र ॥
सरकार के सचिव।

Attention: Accounts Officer
Tangra Jehan Circle
Patna

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

(12)

पत्रांक

प. 27/ वि.नं. 13/2002 दि.

पटना, दिनांक- 31/3/03

सेवा में

अधीनस्थ
रूप से
परामर्शित।

महालेखाकार,
विहार एवं आरखंड
मो. - डि. न्यू रोधी ।

विषय - वि. विभाग ।

विषय - वित्तीय वर्ष 2002-03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संवर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 25.00 करोड़ रुपये में से 2.00 करोड़ (दो करोड़) व्यय की स्वीकृति ।

331 P/226

04.31.3.03

महोदय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2002-03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को संवर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 25.00 करोड़ रुपये में से 132/33 के.वी. का ग्रीड उपकेंद्र शेरघाटी, 132 के.वी. द्विपरिपक्षीय संचरण लाइन के लिए 14.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये मात्र व्यय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है ।

2. यह राशि बजट शीर्ष-6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार-अन्य क्षेत्रीय उप योजना-300-विद्युत पर्वत को उधार-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण विपत्र कोड-6001000300101 के रूप में वित्तीय वर्ष 2002-03 के उपबंधित राशि से आवंटन के आधार पर विकलनीय होगा ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एफ-4-98-88-3881 दिनांक 7.7.1988 के अनुसार पूर्व में दिये गये ऋण के मूल एवं सूद की बाबत प्रसंगाधीन राशि से 25% की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दायनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्वत को छुट दी जाती रही है, जो जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

ऋण की शर्तें निम्नवत होगी :

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा इसमें पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि के एक साल बाद से प्रारम्भ होगी ।

(ख) इस ऋण पर 13% की दर से वार्षिक व्याज देय होगा ।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5% की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा ।

4. इस राशि की निकासी मुख्य अभियन्ता के सचिव (प्रा.) ऊर्जा विभाग के द्वारा रायिवाला कोषागार, सिंघाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को किया जायेगा ।

किरी या पारिश्रमिक से इस सचिव का व्यव अन्य परियोजना में नहीं किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्र.) ऊर्जा विभाग, पटना के पत्राचार से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
80/-
सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

आपांक-प्र.2-वि.बोर्ड-16/2002

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

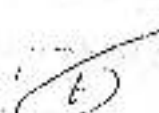
80/-
सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

आपांक- प्र.2-वि.बोर्ड-16/2002

पटना, दिनांक- 31/3/83

प्रतिलिपि :- (सादस्त-वित्त), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्र.), ऊर्जा विभाग/निबंधक/प्रशाखा 7/ वज्र शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, वज्र शाखा/प्रशाखा-7, वित्त/राजस्व शाखा, वित्त/ सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

31/3/83
सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

 31/3/83

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

पत्रांक-प्र2/बोर्ड-विविध-उत्पादन/निधि/06-07

पटना, दिनांक -

14/39/24.03.11

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह-उत्पादित विद्युत सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाइन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 7.99 (सात करोड़ निन्यानवे लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के स्तर पर दिनांक 13.11.2006 एवं दिनांक 17.04.2007 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सह-विद्युत सयंत्रों से उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाइन के निर्माण की लागत राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य में स्थापित मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज (बेतिया) एवं मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिद्धवलिया (गोपालगंज) चीनी मिलों के सह उत्पादित विद्युत सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाइन का निर्माण हेतु राज्यादेश संख्या 794 दिनांक 17.03.2009 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 876.23 (आठ करोड़ छिहत्तर लाख तेइस हजार) लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है।

3. उपर्युक्त आलोक में राज्यादेश संख्या 4693 दिनांक 03.12.2010 द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह-उत्पादित विद्युत सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाइन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई एवं स्वीकृत राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दिया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस योजना के लिए शेष राशि 7.99 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजना उद्ध्यय निर्धारित किया गया है।

5. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह-उत्पादित विद्युत सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाइन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 7.99 (सात करोड़ निन्यानवे लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

7. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना मॉड सं0-10-विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आई0-135/F8 दिनांक-03.03.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड-विविध-उत्पादन/निधि/06-07

दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड-विविध-उत्पादन/निधि/06-07 1439

दिनांक 24/3/11

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप-लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

4693/03.12.2010

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग



पत्रांक 4693/बोर्ड-विविध-उत्पादन/निधि/06-07

पटना, दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह-उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के०भी० संचरण लाईन एवं 132 के० भी० बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5(पांच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के स्तर पर दिनांक 17.10.2006, 13.11.2006 एवं दिनांक 17.04.2007 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सह-विद्युत संयंत्रों से उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन के निर्माण की लागत राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

2. राज्य में स्थापित मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज (बेतिया) एवं मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिद्धवलिया (गोपालगंज) चीनी मिलों के सह उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन का निर्माण हेतु राज्यादेश संख्या 794 दिनांक 17.03.09 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 876.23 (आठ करोड़ छिहतर लाख तेइस हजार) लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है।

3. वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) ने सुगौली एवं लौरिया चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लिया है एवं इनके संयंत्रों का जीर्णोद्धार अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना है। इन दोनों परियोजनाओं से सह-विद्युत उत्पादित विद्युत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निकटतम विद्युत उपकेन्द्रों क्रमशः मोतिहारी एवं रामनगर को 13 मेगावाट (प्रत्येक परियोजना) 132 के०भी० के स्तर पर उपलब्ध किया जाना है। अन्य तीसरा चीनी मिल हरिनगर से भी सह-उत्पादित बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि फरवरी, 2011 तक चालू हो सकेगा एवं निकटतम रामनगर ग्रीड उप केन्द्र में 11 मेगावाट बिजली प्राप्त हो सकेगी।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह-उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के०भी० संचरण लाईन एवं 132 के० भी० बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5(पांच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

1994/PVA(R)

7/12/10

2555/FCR
8/12/101870/H(F&R)
22-12-10

551/FCR

7.12.10

FCR (R)

2/11/10

DCA (am)

2/11/10

17/04/11

17/04/11

17/04/11

17/04/11

17/04/11

5. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण की पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-800-विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण राज्य योजना मांग सं-10-विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आई0 578 ब03 दिनांक 23.11.2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

लगातार

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड-विविध-उत्पादन/निधि/06-07 4693 दिनांक 3/12/10

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

3.12.10

82/114
31-3-07

1107-21/11
T-5

ऊर्जा/बाढ़-कृषि-24/07

पटना, दिनांक -

प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार।

मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक),
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

DLCE
2245
✓ 2245-0008
21/3

विषय:

वित्तीय वर्ष 2008-09 में कोशी बाढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा ट्रांसफार्मर, पोल, भी०सी०डी०एस०, कन्डक्टर, आदि के मरम्मत हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गैर योजना मद से बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण शहरी के अन्तर्गत आवंटित राशि 2784.00 (सत्ताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान हेतु 2784.00 (सत्ताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये मात्र का उप उपपट्टन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभाग के आवंटन संख्या

1/ - 00-0-3-49/13-130/आ0प्र0 दिनांक 21.3.2009 को शुद्धिपत्र संख्या 117 दिनांक 25.3.2009 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008-09 में कोशी बाढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा ट्रांसफार्मर, पोल, भी०सी०डी०एस०, कन्डक्टर, आदि के मरम्मत हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गैर योजना मद से बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण शहरी के अन्तर्गत आवंटित राशि 2784.00 (सत्ताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान हेतु 2784.00 (सत्ताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये मात्र का उप उपपट्टन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जा रहा है।

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में गैर-योजना मद के बजट मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण शहरी-उप मुख्य शीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि के उप शीर्ष-000-अन्य व्यय, उप शीर्ष -0008-क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु बिहार बजट एन 2245-00033003 के अन्तर्गत इतीय अनुपूरक के उपबंधित राशि से विकल्पीय होगा।

3. इस राशि की निकाली समिजाजय कोषागार सिवाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि की निकाली से आवंटित विपदा पर मुख्य-व्यय शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि के उप शीर्ष-000/उपशीर्ष तथा विपदा फंड का उल्लेख राशि उप से की जायेगी बिना पर राशि शीर्ष/उपशीर्ष पर गौर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के अपूर्ण वर्गीकरण की राशि निकाली से निकाली एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

69/114
31-3-07

FC-E
CE(PH)

1610/FCO
31-3-07

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के झापांक 2561 [वि०(2)] दिनांक 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकारी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2237/आ0प्र0 दिनांक 20.08.2008 द्वारा वित्त विभागीय झापांक 2561 [वि० (2)] दिनांक 17.4.1998 की कड़िका 10 के आलोक में ₹ 10,000/- से अधिक अग्रिम राशि की निकारी से संबंधित विपत्रों को पारित करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008-09 तक प्रभावी रहेगा।

6. यदि उपर्युक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 31.3.2009 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकारी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

7. निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकारी नहीं करेंगे। इस राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जाएगा।

विश्वारामाजन,

60/-

प्रधान सचिव

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

झापांक _____

दिनांक _____

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिविल भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

60/-

प्रधान सचिव

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

झापांक _____

दिनांक _____

प्रतिलिपि अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अपर आयुक्त, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय कजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/कजट शाखा वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

60/-

प्रधान सचिव

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

समाप्त

(21) FCI

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

44

दिनांक 22/03-09

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ एवं विभागीय विद्युत पर आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. यह आवंटन ऊर्जा विभाग के पत्रांक 42 दिनांक 06.01.2009 एवं आपके पत्रांक 208 दिनांक 5.12.08 के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन 2008-09 में उपयोजित राशि से कांश बढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा- ट्रान्साफार्मर, पोल, मीटर, सीएसओ, कंडक्टर आदि के मरम्मत हेतु ऊर्जा सेक्टर को निर्गत किया जा रहा है। सारे जल व्यय विभागीय गानवर संख्या 2462/आ0प्र0 दिनांक 12.08.2007 के आलोक में सुनिश्चित की जाय एवं जो इस व्यय की रूकना इस विभाग को भी दी जाय।

2. आवंटित राशि का उचित तरीके में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जिम्मेदार होंगे। जहाँ तक गई राशि का उपयोग होता है, न्याय कार्यालय बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोजिता न्यायिक मद सरकार के विद्युत पत्र में उपयोजिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करें।

प्रधान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

दिनांक

विद्युत विभाग संज्ञा नं.
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित। विषय:

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को 22.36 करोड़ (बाइस करोड़ छत्तीस लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।
स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132/33 के०भी० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132/33 के०भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र को 2x10 एम०भी०ए० के ट्रांसफार्मर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के०भी० एवं 11 के०भी० केबुल फीडरों एवं 33 के०भी० ओवर हेड लाइन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत् आपूर्ति बाधित नहीं हो।

2. उपर्युक्त आलोक में 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में राज्यादेश संख्या-1490 दिनांक 25.03.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्यादेश संख्या-1472 दिनांक 29.03.2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को 50 (पचास) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को 22.36 करोड़ (बाइस करोड़ छत्तीस लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नमुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

0(F)
DISM
EdRow ✓
CE (Pg. / CE (Pg. /

विद्युत निदेशक
13.12.2010

1479/cmb
14/12/13

04mll
S. mll
19/12

3. राज्य का वित्त का भुगतान नहीं हो सके तो विभाग में राज्य सरकार के नीचे महापत्र/संज्ञिद्धों की राशि से अतिदेय/दण्ड राशि का प्रत्युत्ती कर सकेंगे।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड-II-0000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 8801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं०-10-विपत्र फोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 449,58,96,000.00 (चार सौ सनचास करोड अनावन लाख छियानवें हजार) रूपय वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या-542 दिनांक-01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के य०आस० संख्या 207 दिनांक 06.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापक प्र०2/बोर्ड विविध-53/2010

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 12/2/13

ज्ञापक प्र०2/बोर्ड विविध-53/2010 716

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राज्य शाखा, वित्त विभाग, पटना/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/ उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

656/FCR
14-2-13

विद्युत संचरण
कक्षा विभाग

पटना, दिनांक

बिहार विभाग द्वारा
अनुपचारिक रूप
से परामर्शित।

फाइल नं. - 302 / बार्ड - विविध - 35 / 10

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

टेहटा (जहानाबाद) एवं इमानगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के०भी० ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 22.53 (बाईस करोड़ तिरपन लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण, निमित्त संचरण की संरचना में व्यापक विस्तार हो रहा है। संचरण प्रणाली में बढ़ते हुए विद्युत मांग के आलोक में टेहटा (जहानाबाद) एवं इमानगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के 132/33 के०भी० ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० द्वारा अनुरोध किया गया है। टेहटा (जहानाबाद) में ग्रिड सब स्टेशन एवं पटना-गया 132 के०भी० संचरण लाइन से जोड़ने हेतु LILO व्यवस्था के निर्माण के लिए 18.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। इस प्रकार इमानगंज (गया) में ग्रिड सब स्टेशन एवं इमानगंज-शेरघाटी संचरण लाइन के निर्माण के लिए 32.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। अतः इस योजना की कुल लागत 51.20 करोड़ रुपये है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 4607 दिनांक 30.11.2010 द्वारा टेहटा (जहानाबाद) एवं इमानगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के 132/33 के०भी० ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को 1 (एक) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्यादेश संख्या 3609 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 27.07 (सत्ताईस करोड़ सरसठ लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में पुनः टेहटा (जहानाबाद) एवं इमानगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के०भी० ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 22.53 (बाईस करोड़ तिरपन लाख) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नमुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

2(F)
CE/TO
CE(PH)
FC(Rev)✓

107/107

11/02/2013

1475/CMO
14/02/13

633/FC(R)
14-2-13

Amulya
14/2

S.M.C.

1/12

5. यह राशि बजट शीर्ष संकेत-II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य राज्य - राजस्व परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जमियों के लिए, बिहार घटक योजना, उप शीर्ष-0104 बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लि० को ऋण-राज्य योजना भाग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801007890104 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या-543 दिनांक-01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 291 दिनांक 05.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

झापांक प्र०२/बोर्ड विविध-35/2010

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 12/2/13

झापांक प्र०२/बोर्ड विविध-35/2010 726

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - 502/बोर्ड-विद्युत 57/10

पटना, दिनांक



सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

एकमा (सारण) में 132/33 के०भी० मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1 करोड़ (एक) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।

स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के वितरण प्रणाली के सृष्टीकरण, संवर्ण एवं वितरण डानी में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के०भी० मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

उक्त आलांक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 4805 दिनांक 30.11.2010 द्वारा बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के०भी० मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः राज्यादेश संख्या 3611 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 3.10 करोड़ (तीन करोड़ दस लाख) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में पुनः एकमा (सारण) में 132/33 के०भी० मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 1 करोड़ (एक) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

D(F)
D(North)
D(Te)
E(Rov)
E(Rov)

1473/CMD
14/02/13

545/MO(M)
14/02/13

713/FCR
18-2-12

06.m.11

19/2
SMW

6. बिहार पटना के लिए विशेष बटक योजना, उप शीर्ष 0104 बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को ऋण-योजना भाग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 8801007890104 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रुपये। द्वितीय वर्ष 2012-13 के लिए बिहार आकरिगकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या-543 दिनांक-01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०टी०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 298 दिनांक 05.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-57/2010

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 12/2/13

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-57/2010 728

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

जिला विभाग
द्वारा
अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित।

संख्या-102/2012 दिनांक-18/10/12
सेवा नं.

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को वित्तीय वर्ष 2012-13 में ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

आदेश:

वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जन्दाहा अवस्थित पावर सब स्टेशन भी विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं है। जन्दाहा की दूरी भी कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से अधिक है। इस कारण भी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बिजली बाधित रहती है। जन्दाहा कृषि आधारित एक बड़ा क्षेत्र है। जहाँ बिजली की संतोषजनक व्यवस्था के लिए ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जन्दाहा के 10-15 कि०भी० की परिधि में कई पावर सब स्टेशन अवस्थित हैं जन्दाहा में ग्रिड उन्हें एक सुदृढ़ श्रोत प्रदान करेगा। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये लागू होने की संभावना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या 3427 दिनांक 18.08.2010 द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना 25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः राज्यादेश संख्या 3612 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 10 (दस) करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में पुनः वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड-II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104 बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801007890104 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या-543 दिनांक-01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

(F)
D/S
F/T
F/R
F/C
F/P
F/S
F/L
F/B
F/O
F/A
F/I
F/E
F/N
F/J
F/K
F/L
F/M
F/N
F/O
F/P
F/Q
F/R
F/S
F/T
F/U
F/V
F/W
F/X
F/Y
F/Z

1481/CM
14/02/13

261/FC(X)
14-2-13

Sim (W)
19/2

इस दृष्टि को लेकर मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), 3-री फ्लोर, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से एक इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 300 दिनांक 05.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-18/2010

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 12/2/13

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-18/2010 731

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/ उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र० 2/बोर्ड विविध -53/2010

पटना, दिनांक - _____

वित्त विभाग सेवा में,
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 50 (पचास) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132/33 के०भी० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132/33 के०भी०, 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र को 2x10 एम०भी०ए० के ट्रांसफार्मर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के०भी० एवं 11 के०भी० केबुल फीडर्स एवं 33 के०भी० ओवर हेड लाईन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत् आपूर्ति बाधित नहीं हो।

2. उपर्युक्त आलोक में 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में राज्यादेश संख्या-1490 दिनांक 25.03.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में 4 (चार) चालू योजनाओं के लिए कुल 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजना उद्ध्यय योजना एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

4. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 50 (पचास) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना गौन सं०-10-विपत्र कोड पी० 68010080000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114903 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN-0000153 आर०सी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृतिदेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 1510 (सचिव, व्यय) दिनांक 29.03.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड विविध --53/2010

दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड विविध --53/2010

1472

दिनांक

29/3/12

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/मुख्य अभियंता, योजना, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

1490/25.03.2011

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०2/बोर्ड विविध-53/2010

पटना, दिनांक -

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132/33 के०भी० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132/33 के०भी०, 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र को 2x10 एम०भी०ए० के ट्रांसफार्मर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के०भी० एवं 11 के०भी० कंबुल फीडरों एवं 33 के०भी० ओवर हेड लाईन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत् आपूर्ति बाधित नहीं हो। इस परियोजना की कुल लागत 77.36 करोड़ रुपये है।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के० भी० 2x50 एम०भी०ए० मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र आर०के० नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के० भी० 4x50 एम०भी०ए० ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के०भी० 2x10 एम०भी०ए० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस शर्त पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

8. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में उपबधित राशि से विकूलनीय होगा।
9. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।
10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बोर्ड विविध -53/2010

दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बोर्ड विविध -53/2010

14/10

दिनांक

25/3/11

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र2/बीड-विविध-93/10

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग
द्वारा -
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बागमती नदी के तटबंधों का विस्तार और बाढ़ निरोधक कार्य होने से 132 के0 भी0 संचरण लाइनों के टावरों की ऊँचाई कम हो गयी है। इन टावरों की ऊँचाई बढ़ाने से संचरण लाइन के सुरक्षित रूप से कार्य करने एवं जान-माल की क्षति रोकने हेतु सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत आठ 132 के0 भी0 संचरण लाइन के टावर एवं छः पाइल फाउन्डेशन तथा दो आपेन फाउन्डेशन का निर्माण किया जाना है।

2. जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती बांध योजना का विस्तार का कार्य किया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा अविलम्ब टावरों की ऊँचाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिए बागमती तटबंध विस्तार योजना को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राम-विकास योजना के अन्तर्गत रुन्नीसैदपुर में निर्माणाधीन ग्रीड उपकेन्द्र से विद्युत् आपूर्ति चालू की जा सकेगी तथा ग्रीड उपकेन्द्र को एस0के0एम0सी0 हॉस्पिटल में बनने वाले ग्रीड को जोड़ा जा सकेगा।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण-राज्य योजना माँग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या-1631/ सचिव (व्यय) दिनांक-23.03.2011 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-93/10

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-93/10

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव-(प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)



4605/30.11.2010

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रक्राक-प्र02/बोर्ड-विविध-57/10

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग, द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित। सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

आदेश:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली के सृद्धीकरण, संचरण एवं वितरण हानि में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- (क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800 विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष-0101 बिहार राज्य विद्युत परषद को ऋण-राज्य योजना मांग सं0-10 विपत्र कोड-पी. 6801008000101 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या-568एफ08 दिनांक-18.8.2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4605 दिनांक 30/11/10

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा-8 वित्त विभाग/ मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

ऊर्जा विभाग

30/11/10